

## राजस्थान ने शहरी रोज़गार योजना का नए नगर नक़ायों तक वसितार कयिा

### चर्चा में क्य़ों?

हाल ही में ग्राम पंचायतों को शहरी स्थानीय नक़ायों में परिवर्तित करने के बाद रोज़गार के अवसर ख़ो चुके ग्रामीणों के लयिे एक बड़ी जीत में, राजस्थान सरकार 42 नव-नरिमति नगर परषिदों में **शहरी रोज़गार गारंटी योजना** शुरू करने पर सहमत हुई है।

### मुख्य बदि:

- **नगर परषिदों में गारंटीकृत रोज़गार कार्य:** स्थानीय स्वशासन वभिाग ने 27 ज़िलों में नवगठित नगर परषिदों में गारंटीकृत रोज़गार कार्य शुरू कयिे हैं। अधिकारियों के नयिमति पद सृजति होने तक परषिदों के नकिततम शहरी नक़ायों को प्रभारी के रूप में नामति कयिा जाता है।
- **ग्रामीणों की चतिाएँ:** पछिले वर्ष जुलाई में शहरी स्थानीय नक़ायों में परिवर्तित ग्राम पंचायतों में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना** के तहत कार्य रोक दयिा गया था, जसिसे ग्रामीण प्रभावति हुए जो **आजीवकि के लयिे इस योजना** पर नरिभर थे।
- **अनश्चितिकालीन धरना:** रोज़गार कार्यों को फरि से शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जनवरी के अंत में भीम में अनश्चितिकालीन धरना शुरू कयिा
- **राजस्थान असंगठति मज़दूर संघ की भूमकि:** आंदोलन का नेतृत्व **मज़दूर कसिान शक्ति संगठन (MKSS)** से जुड़े राजस्थान असंगठति मज़दूर संघ ने कयिा था, जो **सूचना के अधिकार** आंदोलन में अपनी भूमकि के लयिे जाना जाता है।
- **शहरी रोज़गार गारंटी योजना:** सतिंबर 2022 में कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को सालाना 100 दिन का कार्य देकर आर्थकि सहायता प्रदान करना है।
- **ज्जापन प्रस्तुत:** प्रतभिागियों ने खंड वकिस अधिकारी को एक ज्जापन सौपा, जसिमें भीम नगर परषिद में शीघ्र जॉब कार्ड जारी करने और कार्य आवंटन का आग्रह कयिा गया।
- **कार्यों के प्रकार:** योजना के तहत कार्यों में वृक्षारोपण, तालाब की सफाई, कचरा संग्रहण, पृथक्करण और आवारा जानवरों को पकड़ना शामिल है।

### शहरी रोज़गार गारंटी योजना

- **पूर्व प्रधानमंत्री इंदरिा गांधी** के नाम पर शहरी रोज़गार गारंटी योजना, शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थकि सहायता प्रदान करने के लयिे सतिंबर 2022 में राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी।
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतविर्ष 100 दिन का रोज़गार प्रदान कयिा जाएगा।
- राजस्थान सरकार ने इसे वर्ष 2006 में केंद्र में शुरू की गई ग्रामीणों के लयिे **मनरेगा** की तर्ज पर शहरों में रहने वाले लोगों को गारंटीकृत रोज़गार देने वाली देश की सबसे बड़ी योजना बताया था।
- **शहरी स्थानीय नक़ायों** की सीमा के भीतर रहने वाले **18 से 60 वर्ष की आयु** के लोग चहिनति क्षेत्रों में रोज़गार मांगने और प्राप्त करने के पात्र हैं।